

(27)

राज्य शासन द्वारा
समाप्त कृत्यादि विभाग



(4)

समांक: एफ। 11। 4। आर। डी। 4/5 वि/43566-635

जयपुर, दिनांक: 13. 11. 2010

.....
.....

.....
.....

विषय: उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्रों का तत्वापन/स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रिय आयोग के तीसरे प्रतिवेदन में निहित निम्नलिखित सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में निवेदन है कि जाति, संसुदाय संबंधी प्रमाणपत्रों के उचित तत्वापन हेतु आसपास लोग उठाने के लिए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के इरा में वैधानिक तंत्रधानों में प्रवेश के साथ प्रमाण पत्रों को जांच करना और भी आवश्यक है जहाँ जाति के दूरे प्रमाण पत्रों वाले उम्मीदवार वर्ग: गुणा उम्मीदवारों को ज्ञान और कौशल प्राप्त करने तथा बाट में रोजगार प्राप्त करने के अर्थ में सहायता कर सकते हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उनके अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के होने के समर्थन में प्रस्तुत जो भी प्रयत्नकृत्या साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सके, के आधार पर अर्थात् रूप से निगूक किया जाना चाहिए तथा इस तरह के दावों को स्वीकृत होने से उन स्थानों के लिए, कक्षाओं के प्रवेश से तत्पापित किया जाना चाहिए जहाँ के वे तथा उनके परिवार समाप्त: निवासों है, यदि किसी मामले निवेदन तत्वापन करने से यह पता चलता है कि उम्मीदवार का दावा झूठा है तो उसी सेवाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए।

विशेष प्राधिकारों द्वारा नियुक्त प्रस्ताव में निम्नानुसार एक संज्ञा
 परिभाषित किया जाना चाहिए:-
 "जन्म प्रमाण प्रतीक" है तथा जाति/जनजाति प्रमाण पर उचित माध्यमों
 से प्रमाणित होने के अभाव में और उत्पन्न करने पर यदि यह पता
 चलता है कि अनुचित जाति तथा अनुचित जनजाति के भी मामला है, तो
 संबंध होने का दावा रूखा है तो बिना किसी कारण बताए तथा रूखा प्रमाण
 पर प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत वेतों का
 जो जो जा. नली है, के बारे में सुविग्रह के घिन सेवारत न प्राप्त कर ले
 नार्यों

आ: जाति प्रमाण नहीं के उत्पन्न करने के संबंध में उल्लिखित अनुदेशों का
 अंश से पालन करवाने का उद्देश्य है।

अधीन
 (५)
 विभिन्न शासन अधिकारी